शिक्षित बनो ! संगठित रहो !! संघर्ष करो !!!

Supreme Council of India

(A Council to Save the Constitutional Right for Social Justice)

सुप्रीम काउंसिल ऑफ इण्डिया

(A Wing of Rashtriya Shoshit Parishad Regd.)

JAI BHAGWAN JATAV
Convener
Mob : 9810634677, W : 9810634655
Resi. : 011-2619066
E-mail : scindia.rsp@gmail.com

B-2 Extn./2,
St. No. 7, Krishna Nagar,
Safdarjung Enclave,
New Delhi-110 029

Ref. No. : F. No. SCI/2019/BS/ **Date ....05th June, 2019**

<u>भीम संसद</u>

आदरणीय श्री / श्रीमती

....

....

विषय : दलित समाज के सभी संगठनों, बुद्धिजीवियों, व्यापारियों, प्रतिष्ठित व्यक्तियों को आमंत्रण हेतु सूची तैयार करने के सम्बन्ध में

मान्यवर / महोदय,

आपको समाज का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति मानते हुए आपसे निवेदन करते हैं कि वर्तमान समय की परिस्थितियों का आंकलन करते हुए यह जरूरी हो गया है कि देश के दलित वर्गों के सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिल्ली बुलाकर इस भयंकर स्थिति से निवटने के उपायों पर सलाह–मशवरा लिया जाये। यह तभी सम्भव है जबकि दलित वर्ग के संगठनों, कर्मठ कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों, प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम / पते की सूचियां हमारे पास उपलब्ध हो। अतः आपसे आग्रह हैं कि छोटे–बडे का भेदभाव भुलाकर "अहम" को त्याग कर, दलित समाज के मान–सम्मान एवं चहुमुखी विकास हेतु सामूहिक रूप से विचार विमर्श हो तथा सांझा न्यूनतम कार्यक्रम (Common Minimum Programme) के तहत एक जुटता दिखाते हुए, कार्य करें। हमें यह याद रखना चाहिए कि संविधान के माध्यम से बाबा साहेब डॉ0 अम्बेड़कर जी ने जो हमें दिया है वह भी, अभी तक हम ले नहीं पाये हैं। यदि अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग को सरकारी / अर्धसरकारी नौकरियों, शिक्षा एवं अन्य क्षेत्रों में मिलने वाली आरक्षण इत्यादि की सुविधाएं समाप्त हो जाये तो ऐसी स्थिति बनने पर हमारा दलित समाज कैसे मुकाबला (Survive) करेगा। ऐसी अनेकानेक ज्वलन्त समस्याएं हमारे सामने है।

दलित समाज का हर व्यक्ति दिल्ली की ओर नजर गड़ाये देख रहा है कि दिल्ली से समाज के लिए क्या दिशा निर्देश आते हैं किन्तु दिल्ली में रहने वाले हमलोग आँखें बन्द किये बैंठे हैं। दलित समाज का सम्मानजनक जीवन, अत्याचारों / वीभत्स हत्याकांण्डों का मुकाबला, बेहतरीन शिक्षा, सुरक्षा एवं आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु कोई ठोस योजना अभी तक भी तैयार नहीं हुई है। जिससे कि समाज के चहुंमुखी विकास को सही दिशा निर्धारित की जा सके। जबकि दलित वर्गों के प्रति सरकार का रवैया सकारात्मक (Positive) न होकर अधिकांशतः नकारात्मक (Negative) ही रहा है। सरकार के ऐसे कदमों से यह साफ है कि इन वर्गों को असभ्य मनुवादी व्यवस्था लागू करके, उसी निचले स्थान पर ढ़केल दिया जाये, जहाँ से कि ये वर्ग उपर उठे हैं। आप जानते ही हैं कि गॉव, देहातों में जो दयनीय स्थिति इन वर्गों की बनी हुई है वह बहुत ही भयावह है। हम दिल्ली मे रहने वाले लोग सम्पन्न जरूर हो सकते हैं परन्तु खतरा हमारे सिर पर भी बराबर का ही मंडरा रहा है। हमारे कुछ लोग अपनी जातियां छुपा कर अन्य वर्गों के बीच में रहते हैं और वे समझते है कि पडोसी या अन्य वर्ग के लोग उन्हें पहचानते नहीं हैं, वे इस भुलावे में हैं। उनकी जन्म कुण्डली पडोसियों के पास मौजूद है। हमारे परिवार शहरों में छिटके हुए रहते हैं। कोई भी बस्ती इस प्रकार की नहीं हैं जहाँ कि हम इनका मुकाबला कर सकें। हमें सन् 1984 में सिखों के साथ हुए अत्याचारों व सामूहिक हत्याओं को नहीं भूलना चाहिए। मुसलमानों के साथ मलियाना (मेरठ), मुज्जफरनगर जैसे कांडों को भी नहीं भूलना चाहिए। हमारा समाज सामुहिक अत्याचारों को झेलने के लिए, किसी प्रकार से भी तैयार नहीं है और गदर का किसी भी रूप में जबाव देने में सक्षम ही नहीं है। इसीलिए यह जरूरी है कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक विषयों पर गहनता से विचार विमर्श हो। यह तभी संम्भव है जबकि हमारे समाज के लोग **"झूठे अहम"** को छोड़कर मन से जुड़ जाये और कुछ ठोस फैसले लें एवं समाज को ऐसी भयावह स्थिति से निवटने के लिए तैयार करे। एक दूसरे पर छींटाकसी, बुराई या शिकायत करने से बचे। **इस संकट की घड़ी में आपके बहुमुल्य सुझाव आमंत्रित है।**

इसलिए आपसे आग्रह है कि आप समाज के ऐसे उपरोक्त सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम, पते, मोबाइल नम्बर, इमेल इत्यादि जो भी संम्भव हो इस पत्र के मिलने के 10 दिनों के अन्दर–अन्दर अपने जानकारों में से 02, 04, 10, 25, 50, 100 या जो महानुभाव भी आपकी सूची / जानकारी में हो, उनकी सूची बनाकर भेजने का कष्ट करें। जिससे कि बुद्धिजीवियों / प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उच्चस्तरीय बैठक दिल्ली में तुरन्त बुलाई जा सके। उम्मीद है कि आप अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और हमें निराश नहीं करेंगे।

धन्यवाद सहित,

निवेदकः

Bhagwan

(जय भगवान जाटव)

संयोजक

Email: (i) indiarsp@gmail.com
(ii) jaibhagwanjatav@gamil.com
website: scstparishad.org

(DO IT NOW - DON'T SAY WILL DO IT)

शिक्षित बनो !

संगठित रहो !!

संघर्ष करो !!!

Supreme Council of India

(A Council to Save the Constitutional Right for Social Justice)

सुप्रीम काउंसिल ऑफ इण्डिया

(A Wing of Rashtriya Shoshit Parishad Regd.)

JAI BHAGWAN JATAV
Convener
Mob : 9810634677, W : 9810634655
Resi. : 011 26192066
E-mail : scindia.rsp@gmail.com

B-2 Extn./2,
St. No. 7, Krishna Nagar,
Safdarjung Enclave,
New Delhi-110 029

F. No. SCI/2019/Conference/

Ref. No. :

Date 07th Oct., 2019

<u>भीम संसद</u>

आदरणीय श्री/श्रीमती

....

....

विषयः देश के दलित समाज के गैर राजनैतिक संगठनों, बुद्धिजीवियों, व्यापारियों, प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भीम संसद के प्रथम सत्र 2019 के लिए एक सांझा न्यूनतम कार्यक्रम की रूप रेखा तैयार करने, कमेटियों का गठन करने हेतुः आम बैठक

महोदय,

आपको समाज का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति मानते हुए आपसे निवेदन करते हैं कि वर्तमान समय की परिस्थितियों का आंकलन करते हुए यह जरूरी हो गया है कि देश के दलित वर्गों के सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिल्ली बुलाकर इस भयंकर स्थिति से निवटने के उपायों पर सलाह–मशवरा लिया जाये। यह तभी सम्भव है जबकि दलित वर्ग के संगठनों, कर्मठ कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों, प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम/पते की सूचियां हमारे पास उपलब्ध हो। अतः आपसे आग्रह हैं कि छोटे–बडे का भेदभाव भुलाकर "अहम" को त्याग कर, दलित समाज के मान–सम्मान एवं चहुमुखी विकास हेतु सामूहिक रूप से विचार विमर्श हो तथा सांझा न्यूनतम कार्यक्रम (Common Minimum Programme) के तहत एक जुटता दिखाते हुए, कार्य करें। हमें यह याद रखना चाहिए कि संविधान के माध्यम से बाबा साहेब डॉ0 अम्बेड़कर जी ने जो हमें दिया है वह भी, अभी तक हम ले नहीं पाये हैं। यदि अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग को सरकारी/अर्धसरकारी नौकरियों, शिक्षा एवं अन्य क्षेत्रों में मिलने वाला आरक्षण इत्यादि की सुविधाएं समाप्त हो जाये तो ऐसी स्थिति बनने पर हमारा दलित समाज कैसे मुकाबला (Survive) करेगा। ऐसी अनेकानेक ज्वलन्त समस्याएं हमारे सामने है। जिनका कुछ तक समाधान एक साथ मिल बैठकर ही ढूंढा जा सकता है।

दलित समाज का हर व्यक्ति दिल्ली की ओर नजर गड़ाये देख रहा है कि दिल्ली से समाज के लिए क्या दिशा निर्देश आते हैं किन्तु दिल्ली में रहने वाले हमलोग आँखें बन्द किये बैठे हैं। दलित समाज का सम्मानजनक जीवन, अत्याचारों/वीभत्स हत्याकाण्डों का मुकाबला, बेहतरीन शिक्षा, सुरक्षा एवं आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु कोई ठोस योजना अभी तक भी तैयार नहीं हुई है। जिससे कि समाज के चहुंमुखी विकास के लिए सही दिशा निर्धारित की जा सके। जबकि दलित वर्गों के प्रति सरकार का रवैया सकारात्मक (Positive) न होकर अधिकांशतः नकारात्मक (Negative) ही रहा है। सरकार के कदमों से यह साफ है कि इन वर्गों के ऊपर असभ्य मनुवादी व्यवस्था लाधी जाये एवं हमें उसी निचले स्थान पर ढ़केल दिया जाये, जहाँ से कि दलित वर्ग उपर उठे हैं। आप जानते ही हैं कि गॉव, देहातों में जो दयनीय स्थिति इन वर्गों की बनी हुई है वह बहुत ही भयावह है। हम दिल्ली मे रहने वाले कुछ लोग सम्पन्न हो सकते हैं परन्तु खतरा हमारे सिर पर भी बराबर का ही मंडरा रहा है। हमारे परिवार शहरों में छिटके हुए रहते हैं। कोई भी बस्ती इस प्रकार की नहीं हैं जहाँ कि हम अत्याचारी का मुकाबला कर सकें। हमें सन् 1984 में सिखों के साथ हुए अत्याचारों व सामूहिक हत्याओं को नहीं भूलना चाहिए। मुसलमानों के साथ मलियाना (मेरठ), गुजरात, मुज्जफरनगर जैसे अनेकों कांडों को भी नहीं भूलना चाहिए। हमारा समाज सामुहिक अत्याचारों को झेलने के लिए, किसी प्रकार से भी तैयार नहीं है और गदर की स्थिति आने पर हमारा समाज किसी भी रूप में जबाव देने में सक्षम नहीं हे। इसीलिए यह जरूरी है कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक विषयों पर गहनता से विचार विमर्श हो। यह तभी संम्भव है जबकि हमारे समाज के लोग **"झूठे अहम"** को छोड़कर मन से जुड़े जाये और कुछ ठोस फैसले लें एवं समाज को ऐसी भयावह स्थिति से निवटने के लिए तैयार करें। एक दूसरे पर छींटाकसी, बुराई या शिकायत करने से बचे। **इस संकट की घड़ी में आपके बहुमुल्य सुझाव आमंत्रित है।**

इसलिए आपसे आग्रह है उपरोक्तानुसार एक सांझा न्यूनतम कार्यक्रम (Common Minimum Programme) का खाका तैयार करने गम्भीर समस्याओं का समाधान ढूंढने, आर्थिक कार्यक्रम चलाने, शिक्षा पर विशेष बल देने, अत्याचारों का कैसे मुकाबला किया जाये, आदि विषयों पर तैयारी बुलायी गयी है जो कि **शनिवार 23 रविवार 24 नवम्बर 2019** को होने वाले भीम संसद के सत्र में दिल्ली/एनसीआर वालों की सक्रिय भूमिका तय करने के उद्देश्य से प्रतिष्ठित व्यक्तियों एवं संगठनों की एक अहम बैठक **शनिवार 19 अक्टूबर 2019 को दोपहर 02:00 बजे आन्ध्रप्रदेश भवन के कॉन्फ्रेस हाल, नयी दिल्ली 110001** में बुलायी गयी है। जिन सम्मानित साथियों को सूचना न भी मिल सकी हो, उन्हें भी सूचित कर साथ लाने का कष्ट करें। जिसमें साथियों सहित आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है।

धन्यवाद सहित,

Venue: <u>कॉन्फ्रेस हॉल, प्रथम तल,</u>
<u>आन्ध्र प्रदेश भवन,</u>
<u>1-अशोक रोड़, नई दिल्ली</u> – 110001
<u>शनिवार दिनाक 19 अक्टूबर 2019</u>
<u>दोपहर 02:00 से 06:00 सांय</u>

निवेदकः

Bhagwan

(जय भगवान जाटव)

Email: (i) indiarsp@gmail.com
(ii) jaibhagwanjatav@gamil.com
website: scstparishad.org
Mob: 9810634677, 9810634655 Whatsapp

विचारणीय प्रश्न

जय भगवान जाटव
9810634677

समाज पूछ रहा है – हम कहाँ खड़े हैं।

1. **दशा और दिशा :–** आज का अनुसूचित जाति/जनजाति समाज कहाँ खड़ा है। हमें क्या करना चाहिए, और यह कैसे संम्भव होगा। आप अपने सहयोग की भी स्थिति स्पष्ट करें।

2. **समस्या और सुझाव :–** वर्तमान समय में हमारे वंचित समाज की मुख्य रूप से कौन–कौन सी समस्याएं हमारे सम्मुख हैं और उन समस्याओं के निदान (Solution) पर आपके क्या–क्या ठोस सुझाव हैं। इन समस्याओं के निदान में आपका क्या सहयोग रहेगा।

3. **आरक्षण समाप्ति की ओर :–** हम सभी को पता है कि नौकरियों में आरक्षण बड़ी तेजी के साथ समाप्त होता जा रहा है। राजनैतिक व शैक्षिणिक सहित अन्य सभी प्रकार के आरक्षण पर सरकार की तरफ से आरक्षण की समाप्ति के हर संम्भव प्रयास किये जा रहे हैं। ऐसी कठिन परिस्थिति में हमें क्या करना है और यह कैसे सम्भव होगा। इसमें स्वयं का हमारा सहयोग क्या है या होगा। ठोस सुझाव दें।

4. **सरकार की तरफ से दी जा रही सुविधाएं :–** यदि सरकार द्वारा दी जाने वाली आरक्षण सहित सभी सुविधाएं समाप्त कर दी जाये तो वंचित समाज को अपने स्वयं के स्तर पर क्या–क्या कदम उठाने पडेंगे/चाहिये। जिससे कि हमारा दलित समाज, सामान्य वर्गो के सामने टिका रह सकें। उठाए जाने वाले कदमों के बारे में आपके विचार एंव सहयोग क्या–क्या हैं या रहेंगे।

5. **अत्याचारों से मुक्ति :–** देश में जघन्य अत्याचारों की बाढ़ आयी हुई हैं, मान–सम्मान कैंसे बचाये रखें। अत्याचारों से मुक्ति पाने के उद्देश्यों से हमें क्या–क्या कदम उठाएं जाने की आवश्यकता हैं जिससे कि मान–सम्मान भी बच सके और जघन्य अत्याचारों पर लगाम भी लग सके।

6. **आर्थिक स्थिति :–** वंचित समाज (अनुसूचित जाति/जनजाति) की आर्थिक स्थिति बहुत ही भयानक मोड़ पर आ पहुंची है। वंचित समाज के परिवारों में सरकारी आँकड़ों के अनुसार 42 प्रतिशत कुपोषण तथा 22 प्रतिशत बच्चों में खून की कमी है। शरीर की बनावट, कद–काठी दम तोडती जा रही है। ऐसे कमजोर गरीब परिवारों के प्रति सरकार को छोड़कर समृद्ध परिवारों की क्या–क्या जिम्मेदारियाँ बनती है या समाज का सम्पन्न एवं बुद्धिजीवी वर्ग किस प्रकार का सहयोग कर सकता हैं और कैंसे कर सकता हैं। ठोस सुझाव दें।

7. **राजनैतिक हल :–** दलित समाज के सांसद/विधायक निर्लज, निक्म्मों, निट्ठल्ले साबित हो रहे हैं। स्वार्थवश इन्होंने अपने आपको अपनी–अपनी पार्टियों के पास गिरवी रख दिया है। इन्हें इनकी पार्टियों से कैंसे मुक्त कराया जाये या समाज को क्या–क्या कदम उठाने चाहिए। ठोस सुझाव दें।

8. **वोट का अधिकार :–** बाबा साहेब डॉ. बी. आर. अम्बेडकर जी ने राजा–रानी से लेकर एक गरीब से गरीब मेहतरानी तक समान वोट/मताधिकार का अधिकार दिया था जो इवीएम (EVM) मशीन के द्वारा छिनता जा रहा है। इवीएम (EVM) मशीन से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है जिससे कि हमारा वोट का अधिकार कामय रहे जिससे कि हम अपने मताधिकार का अपनी इच्छानुसार प्रयोग कर सके।

9. **गरीबी एवं अमीरी में भारी अन्तर :–** सरकार की साजिस भरी नीति के अनुसार गरीब और गरीब तथा अमीर और अधिक अमीर होता जा रहा है। गरीब एवं अमीर के बीच की खाई इतनी अधिक बढ़ चुकी है जिसको कि पाटने में बड़ी मशक्त (Effort) की जरूरत पड़ेगी। हमें कौन–कौन से कदम उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। लाखों लुटेरे देश का धन, दौलत लूटकर विदेशों में जा बसे हैं और लाखों लुटेरे देश छोडकर भागने की फिराक में हैं यही नहीं बल्कि उनकी धन दौलत पहले से ही विदेशों में पहुंच चुकी है। सरकार का भरपूर सहयोग इन्हें मिल रहा है। मूलनिवासियों को ऐसे कौन–कौन से कदम उठाने चाहिए जिससे कि देश के मुठ्ठी भर लोगों पर लगाम कसी जा सके और लुटेरे देश से भागने न पायें तथा देश की धन–दौलत सही सलामत बच जाये।

10. **सत्ता पर कब्जा करें :–** देश में अन्धविश्वास चरम सीमा पर है इस समय देश की राजनीतिक स्थिति भी अस्थिर एवं डाँवाडोल है। ऐसी परिस्थिति में सत्ता पर कब्जा करना कोई मुश्किल नहीं है। राजनैतिक परिस्थितियॉ अस्थिर होने कि स्थिति में हमें इसका लाभ उठाना चाहिए वशर्ते कि हम अपने दिमाग की बत्ती जला लें और अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/अल्पसंख्यक समुदाय को संगठित करने में पूरी ताकत झोंक दें तो आसानी से सत्ता पर कब्जा भी किया जा सकता है? यदि किया जा सकता है तो कैसे? इसमें आपका सहयोग क्या रहेगा?

उपरोक्त बिन्दुओं में से किसी एक या कई बिन्दुओं पर या सभी बिन्दुओं पर अपने विचार लिखित में हिन्दी या अंग्रेजी में भेज सकते हैं परन्तु एक बिन्दु पर अपने–अपने विचार अधिकतम 250 शब्दों में ही हो। कृपया वेबसाइड पर अवश्य देंखें।

(जय भगवान जाटव)

E-Mail: indiarsp@gmail.com
Website: scstparishad.org.in

शिक्षित बनो! संगठित रहो!! संघर्ष करो!!!

दिनांकः 19.10.2019

भीम संसद

प्रथम वर्ष – प्रथम सत्र

शनिवार, रविवार, दिनांक 23–24 नवम्बर, 2019 प्रातः 09:30 बजे

डॉ. अम्बेडकर भवन, झंडेवालान, रानी झाँसी रोड, नई दिल्ली

सम्मानित साथियों,

जुलाई 2018 को दिल्ली में दलित महापंचायत बुलाई गयी थी जिसमें दलित समाज के हर वर्ग के हजारों लोगों ने भाग लिया था जिसमें 20 प्रस्ताव पारित किये गये थे। सभी मुद्दों को सरकार के समक्ष उठाया गया था। सरकारी स्तर पर कार्यवाही तो चल रही है, परन्तु सकारात्मक परिणाम अभी तक भी सामने नहीं आये हैं। कारण स्पष्ट है कि दलित समाज, भारत सरकार पर उतना दबाव नहीं बना सका जिससे कि 02 अप्रैल 2018 को गिरफ्तार हुए नौजवानों को बिना शर्त रिहा करा सकता, और न ही शहीद हुए नौजवान भाईयों के परिवारों को उचित मुआवजा ही दिलवा सका, यही नहीं, बल्कि शिक्षा एवं ऋण इत्यादि में आय सीमा के बन्धन के हटवा सका, ज्यूडिशरी कमिशन का गठन हो या गुणवत्ता वाली समान एवं निःशुल्क शिक्षा हो, या खाली पड़े आरक्षित पदों को भरवाना हो या आरक्षण बिल पास करवाना हो, खेतीहर मजदूरों को सरकारी जमीन का आवंटन हो या वजट का समानुपातिक आवंटन हो या आवंटित वजट धनराशि का दुरूपयोग हो, या जाति प्रमाण पत्र को सम्पूर्ण भारत में मान्यता दिलाना हो या भारतीय सेना में आरक्षण का मामला हो या ग्रुप सी एवं डी, की नौकरियाँ को समाप्त करने का मामला हो, या जघन्य हत्याकांण्ड/वीभत्स अत्याचार, नाबालिग बच्चियों से सामुहिक ब्लात्कार एंव हत्या, निर्दोष नौजवानों की निर्मम हत्याएं, आगजनी इत्यादि के मामले हो, या अन्य गंम्भीर से गंम्भीर मामलों तक में भी सजा नहीं मिलती बल्कि अधिकांशतः अत्यन्त गम्भीर मामलों तक में मुकदमें भी दर्ज नहीं हो पाते। चमार रेजीमेंट के गठन का मामला हो या दलितों को आत्मरक्षा के लिए आर्म्स लाइसेंस जारी करने का मामला हो, ऐसी अन्य हजारों गम्भीर समस्याएं हैं जिनका निदान किसी भी बडे से बडे संगठन द्वारा भी नहीं हो पा रहा है। दूसरी तरफ पूंजीपतियों, ब्लात्कारियों, अत्याचारियों एंव दबंगों को बेरोक–टोक आर्मस लाइसेंस दिये जा रहे हैं, जिनका कि इस्तेमाल दलितों के खिलाफ ही किया जाता रहा है। सवर्ण समाज के लोगों के पास भारी संख्या में सरकारी नौकरियां, जमीन जायदाद, व्यापार के ऊपर कब्जा एवं संस्थागत प्रतिष्ठान एवं उद्योग धन्धे तथा शैक्षिणिक संस्थानों, धन–सम्पति पर पूर्ण कब्जा आदि सभी कुछ इन्हीं वर्गो का ही है। जबकि करोड़ों दलित परिवार भूखे पेट ही नहीं सोते बल्कि हर तरह के हथकंडे अपना कर दलित वर्गो को धरातल में पहुंचाने की कोशिश में जुटे हैं। दलित वर्गो को सरकारी नौकरियों एवं शिक्षा इत्यादि से बंचित करने की भरपूर कोशिश जारी है। यह सभी, कुछ यूँ ही नहीं हो रहा है बल्कि इन सभी कृत्यों के लिए हम स्वयं ही जिम्मेदार हैं। यह भी तय होना चाहिए कि आखिर कब तक हम सरकार के सामने हाथ फैला कर भीख मांगते रहेंगे?

उपरोक्त सभी तथ्यों पर गहनता से विचार करने के बाद दलित महापंचायत बुलायी गयी थी जिस में प्रस्ताव पारित किया गया था कि राष्ट्रीय स्तर पर एक संयुक्त मंच का गठन किया जाये जिसका नाम **भीम संसद** के नाम से प्रस्तुत किया गया। भीम संसद का प्रत्येक वर्ग का प्रत्येक सदस्य समान स्तर के होंगें, किसी भी सदस्य का दर्जा बड़ा या छोटा नहीं होगा। **भीम संसद** में दलित समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व होगा। इसमें कोई सन्देह ही नहीं है कि देश के सभी दलित संगठन अपने–अपने क्षेत्रों में बड़ी संलग्नता के साथ तन–मन–धन लगा कर विकास के कार्यो में जुटे हैं, जिसके कारण दलितों में समाजिक जागृति बड़ी तेजी से बढ़ी है। जबकि सरकार की नीति और नीयत भेदभावपूर्ण होने के साथ–साथ दलित विरोधी भी है। इसलिए सभी जागरूक संगठनों एवं बुद्धिजीवियों को ''अहम्'' (मैं) त्याग कर **भारतीय संसद** की तरह ही **भीम संसद** का सम्माननीय सदस्य बनने के लिए प्रबुद्ध व्यक्तियों, बुद्धिजीवियों, डाक्टरों, इंजीनियरों, वकीलों, प्रोफेसरों, कारोबारियों, गैर राजनैतिक संगठनों एंव अन्य सभी जागरूक कर्मठ कार्यकर्ताओं को **भीम संसद** का सक्रिय सदस्य बनने के लिए प्रेरित करने एवं **भीम संसद** का प्रथम वर्ष का पहला सत्र शनिवार व रविवार, दिनांक 23 एवं 24 नवम्बर 2019 को डॉ0 अम्बेडकर भवन, नई दिल्ली के प्रांगण में हो रहा है जिसमें आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। **इसीलिए आग्रह है कि सभी सम्मानित साथियों को इसकी सूचना अवश्य भिजवा दें तथा साथ भी लेकर आयें।**

अपने आने की सूचना अवश्य देने का कष्ट करें। अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर के साथ सीट नम्बर भी प्राप्त कर लें। अपंजीकृत व्यक्ति दर्शकदीर्घा से ही **भीमसंसद** की कारवाई देख सकेंगे।

धन्यवाद सहित,

निवेदक

सुप्रीम कॉउसिल ऑफ इण्डिया

देवेन्द्र कुमार
सहसंयोजक
मो. 7988468571
व्हाटस. 9871402421

E Mail: indiarsp@gmail.com
Website: www.scstparishad.org

जय भगवान जाटव
संयोजक
मो. 9810634677
व्हाटस. 9810634655